

एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वदम प्राप्ता 09R9 CPC सूनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 06/08/25 को पेश हो।

[Signature]
25/8/25

08
25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्राप्ता 09R9 CPC दि. 18/08/25 को पेश हो।

[Signature]
06/8/25

18/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/गण उपस्थित। वदम प्राप्ता के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अचलपदन किया गया। प्रार्थी/गण द्वारा पेश मूल्य रायल्टी का लॉ 693/2004 परकीरी के नाम हरिसीत शर्मा वकील आदेशों/दिनांक 29/09/2016 के अचलपदन से जाहिर है कि प्रकरण प्राप्ता दिनांक 30/8/2008 का परामना में TDR पिडावा के बरकार प्रस्ताव में निम्न चल रही थी। प्रकरण के इस क्रम द्वारा दिनांक 30/8/2008 को प्राप्ता दिनांक जारी की और बुनियादी पूर्ण, TDR पिडावा द्वारा 08 वर्षों के बरकार प्रस्ताव तैयार कर पेश नहीं किया। दिनांक 06/06/2016 की आदेशों/का



के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण
राजस्व लोक अदालत राजस्थान में प्रेषण हुआ
था जहाँ इसे आपपक्ष कारण की अनुपस्थिति
में अदम छावनी, अदम पैली में खारिज
किया गया था जो विभिन्न प्रावधानों तथा
लोक अदालत की मूल भावना के विरुद्ध है।

यह सुझावित सिद्धान्त है कि राजस्व
लोक अदालत या अदालतों में केवल एक
प्रकारों को प्रेषण करना होता है जो आपसी
सहमति एवं राजीनामों के माध्यम से खारिज
किफायती रूप से निस्तारित किये जा सकते हैं।
राजस्व लोक अदालत एक alternative dispute

resolution system है जो सहमति व समझौते के
माध्यम से न्यायलयों में pending cases को
लोगों की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निस्तारित
कर ना केवल न्यायलयों में लंबित मामलों का
बोध कम किया जा सके बल्कि पक्षकारों
को अपने घर से ही सुलभ न्याय प्रदान किया

सके अर्थात् The spirit of the Revenue Lok
adalat is "justice at your doorstep" to provide
Speedy and economical settlement of revenue
suits. Lok adalats promote the spirit of
mitigation and reconciliation whereby the parties
develop respect and understanding for each
other and saving people from lengthy and
costly court proceedings also.



रीख
कम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

राजस्थान लोक अदालतों में अवरुद्धता
प्रकरण को हल नहीं किया जा सकता और
ना ही पक्षकारों के absent रहने पर
प्रकरण को अडम हाफरी, अडम पैरवी में
स्वारिज किया जा सकता है।

In the case of Kripal Singh v/s
state of Rajasthan & Anr. S.B. Criminal Misc
2024 में माननीय सम्प्रधान हाईकोर्ट ने
प्रतिपादन किया है कि " Lok adalat does
not have the power to 'dismiss' a case owing
to default in appearance by parties". The
court highlighted section 20(5) of the Legal
Services Authorities Act 1987 as per which
where Lok adalat is not able to make an award
due to no compromise or settlement being reached
between the parties, the record of the case
needs to be returned.

The apex court in the case of
state of Punjab & Anr. v/s Jalore Singh & ors.
2008 (supra) has also held that "Lok adalats
have no adjudicatory or judicial functions".



प्रकरण में राजस्थान लोक अदालत के
दावलाभों में प्रेश करने की प्रतीति/वासीति
(व प्रतीवासीति) को proper सूचना/नोटिस जारी
होना ही चाहिए नहीं होता है जो Order 5 Rule
9 to 20 के प्रावधानों के विरुद्ध है। अतः प्रकरण को
जी, श्वकारा प्रस्ताव में निरत था, को तकनीकी आधार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म व मेंज
	<p>पर नही बल्कि गुणावगुण के आधार पर मीमाणा करना न्यायोचित होगा।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना का फॉर्म 09 R7 CPC एनीकार किया जाता है। इस न्याय के आदेश दिनांक 06/06/2016 को set-aside किया जाता है। मूल प्रकरण को पीला रिकार्ड से तलब किया जावे। फॉर्म के फिलसुम होकर तलब से कम होकर तलब किये गये मूल रिकार्ड के साथ सत्यता है।</p>	



[Handwritten Signature]

18/8/22

उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला मन्दावाड़ (राज.)